सदस्य बनें
सच और सरोकार की पत्रकारिता से जुड़ें
वार्षिक सदस्यता : ₹ 500 मात्र
पूरा वर्ष अख़बार नि:शुल्क
पैनल विज्ञापन दें
अपने व्यवसाय/संस्था का प्रचार करें 'जन जन विचार' में।
किफायती • प्रभावी • विश्वसनीय
संपर्क : 69001 26012

जन जन की बात जन जन तक

साप्ताहिक

जन जन विचार

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367 ::Guwahati, Friday, 27 March, 2026 :: Vol-11 Year-1 :: शुक्रवार । 27 मार्च 2026 । शक संवत 1948 । चैत्र । शुक्ल । नवमी । :: पृष्ठ-12 । मूल्य - 5 रुपए।

जन चिंतन

'बाहरी' की राजनीति

असम की मिट्टी का इतिहास केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि सह-अस्तित्व से बना है। यह वही धरती है जहां अलग-अलग समय में बिहार, राजस्थान, बंगाल, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों से लोग आए-कुछ रोजगार के लिए, कुछ व्यापार के लिए, और कुछ जीवन बसाने के लिए। यह कोई हालिया घटना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक काल से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है।

राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा द्वारा अपने वरिष्ठ व समर्पित कार्यकर्ता विजय गुप्ता को प्रतिष्ठित सीट मध्य गुवाहाटी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से 'बाहरी' और 'खिलंजिया' की राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि विजय गुप्ता ने दावा किया है कि उनका परिवार 1925 में ही असम आया था और वे 'असम आई' की ही संतान हैं। **शेष पृष्ठ 2 पर**

सेंट्रल गुवाहाटी में तपिश

जन जन विचार
...✍ पटना

असम विधानसभा चुनाव 2026 के तहत सेंट्रल गुवाहाटी सीट इस बार राज्य की सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल सीटों में शामिल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता ने भारी समर्थक जुटान के साथ अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। नामांकन के दौरान सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने यह साफ संकेत दिया कि इस सीट पर मुकाबला भले ही द्विपक्षीय हो, लेकिन राजनीतिक तापमान चरम पर है। विजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर विपक्ष 'खिलंजिया' को वंचित करने का आरोप लगाकर मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश में जुट गया है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। **शेष पृष्ठ 3 पर**

गुप्ता को गढ़ में कुंकी चौधरी की चुनौती

सेंट्रल गुवाहाटी सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। भाजपा के अनुभवी चेहरे विजय कुमार गुप्ता के सामने असम जातीय परिषद की युवा उम्मीदवार कुंकी चौधरी मैदान में हैं, जो कांग्रेस गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं।

विजय कुमार गुप्ता का राजनीतिक सफर करीब 35 वर्षों का रहा है। संगठन में उनकी गहरी पकड़ और क्षेत्र में मजबूत नेटवर्क उन्हें बढ़त दिलाता है। सेंट्रल गुवाहाटी को भाजपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है, और यहां पार्टी का बूथ स्तर तक मजबूत ढांचा उनके पक्ष में जाता दिख रहा है।

दूसरी ओर, कुंकी चौधरी युवा, शिक्षित और नए विचारों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। वे खुद को 'नई राजनीति' का चेहरा बताती हैं और विकास, पारदर्शिता और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही हैं। हालांकि, उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्र में असम जातीय परिषद का कमजोर संगठन और कांग्रेस पर निर्भरता है।

बिहार : 14 अप्रैल के बाद मिलेगा नया मुख्यमंत्री

जन जन विचार
...✍ पटना

बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। नीतीश कुमार का विधान परिषद से इस्तीफा, राज्यसभा जाने की तैयारी और नई सरकार को लेकर बैठकों का दौर-ये सब संकेत देते हैं कि आने वाले हफ्तों में बड़ा राजनीतिक बदलाव संभव है।

पूरा घटनाक्रम

'समृद्धि यात्रा' का समापन- मुख्यमंत्री ने अपनी राज्यव्यापी यात्रा खत्म कर दी है, जो राजनीतिक माहौल को परखने और संदेश देने का जरिया थी।

एमएलसी पद से इस्तीफा तय-संवैधानिक नियमों के तहत राज्यसभा सदस्य बनने से पहले उन्हें विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी।

राज्यसभा में एंट्री-अगले महीने 10 तारीख तक राज्यसभा सदस्य के रूप **शेष पृष्ठ 3 पर**

विस चुनाव : 789 उम्मीदवार मैदान में

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज्य की सियासत निर्णायक दौर में प्रवेश कर गई है। सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 789 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं, जिससे चुनावी तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है।

निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 24 मार्च से शुरू हुई नामांकन जांच मंगलवार को बरपेटा और ढेकियाजुली सीटों पर लंबित मामलों के निपटारे के साथ समाप्त हुई। इस चुनाव में कुल 815 उम्मीदवारों ने 1,389 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 789 उम्मीदवार अब आधिकारिक रूप से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।

ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में सभी 10 नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि बरपेटा में एक नामांकन खारिज होने से अब केवल तीन उम्मीदवार ही मुकाबले में बचे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी महानंद सरकार का नामांकन रद्द होने के बाद यहां मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। अब एजीपी के दीपक कुमार दास का सामना दो निर्दलीय उम्मीदवारों से होगा।

राज्य में चुनावी सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और अब पूरा ध्यान प्रचार अभियान पर केंद्रित है। आगामी 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 4 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

ऐसे में असम की जनता किसे अपना जनादेश देती है, यह देखने के लिए सभी की नजरें अब चुनावी मैदान और मतदाताओं के रुख पर टिकी हैं।

होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने वाले नेवी कमांडर तंगसीरी की मौत!

नई दिल्ली। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल अलीरेजा तंगसीरी की मौत की खबर ने मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा दी है। इजरायली मीडिया ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में बंदर अब्बास में तंगसीरी मारे गए।

अंदर पढ़ें

2. चैती छठ पर उमड़ी आस्था विजय गुप्ता ने लिया आशीर्वाद
3. विपक्ष कहीं नहीं, भाजपा को मिलेगा प्रचंड जनादेश : हिमंत
5. पेट्रोल-डीजल व एलपीजी की कोई कमी नहीं : केंद्र
7. चुनावी शोर बनाम जमीन की सच्चाई
8. ढेकियाजुली : विकास बनाम बदलाव की सीधी टक्कर
9. दाने-दाने को तरसेगी दुनिया
10. क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों का परचम
11. हॉकी वर्ल्ड कप : पाक का ड्रामा शुरू

चैती छठ पर उमड़ी आस्था विजय गुप्ता ने लिया आशीर्वाद

जन जन विचार
...✍ स्पोर्ट्स डेस्क

चैती छठ के पावन अवसर पर सेंट्रल गुवाहाटी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार विजय कुमार गुप्ता ने श्रद्धापूर्वक छठ पूजा में भाग लेकर छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने शुक्लेश्वर छठ घाट पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।

इस दौरान छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से ओत-प्रोत था। विजय गुप्ता ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा में भाग लिया और व्रतधारियों के बीच समय बिताया। उपस्थित महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

उन्होंने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रशासन और स्थानीय संगठनों द्वारा घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

विजय गुप्ता ने सभी श्रद्धालुओं को चैती छठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व समाज में एकता, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। कार्यक्रम के दौरान भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से वातावरण और भी आध्यात्मिक हो गया।

इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिनमें अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह, उपाध्यक्ष एसपी राय, महासचिव अनिल चौधरी, पप्पू शर्मा, अशोक राय, जयराम सिंह, श्याम सुंदर राउत, देवानंद सिंह, तिलकेश्वर झा, राम बाबू चौधरी व 'जन जन विचार' के संपादक धनेश्वर चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

'बाहरी' की राजनीति

1925 के आसपास का समय हो या उसके बाद के दशक-उस समय असम में जो भी लोग आए, वे किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नहीं, बल्कि आर्थिक अवसरों के कारण आए थे। चाय बागानों, व्यापारिक गतिविधियों और प्रशासनिक विस्तार ने बाहरी लोगों को आकर्षित किया। उस दौर में सत्ता ब्रिटिश शासन या बाद में कांग्रेस के हाथों में रही, और राज्य की आर्थिक संरचना में श्रमिकों व व्यापारियों की आवश्यकता स्वाभाविक थी।

आज सवाल यह उठता है कि जो लोग एक सदी से अधिक समय से असम में रह रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां यहीं जन्मी और पली-बढ़ीं, क्या उन्हें 'बाहरी' कहना न्यायसंगत है? क्या किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसकी मूल जड़ों से तय होगी या उस मिट्टी से भी, जहां उसने अपना जीवन खपा दिया?

सच यह है कि असम की सामाजिक बनावट में इन समुदायों का गहरा योगदान है। व्यापार, शिक्षा, प्रशासन और सांस्कृतिक जीवन-हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। कई तो इतने घुल-मिल गए हैं कि उनकी मूल पहचान तक धुंधली हो चुकी है।

भाषा का मुद्दा भी अक्सर राजनीतिक हथियार बन जाता है। असम जैसे बहुभाषी राज्य में हर कोई शुद्ध असमिया बोले, यह अपेक्षा व्यावहारिक नहीं है। बराक घाटी, हाफलोंग, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ जैसे क्षेत्रों में भाषाई विविधता स्वयं इस बात का प्रमाण है कि असम की पहचान बहुलता में ही है।

राजनीतिक अधिकार का सवाल भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। जब असमिया लोग देश के अन्य हिस्सों में जाकर बसते हैं और वहां अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो फिर असम में बसे अन्य भारतीयों को उसी अधिकार से वंचित करना किस हद तक उचित है?

'बाहरी' और 'खिलंजिया' की यह बहस दरअसल राजनीति से अधिक भावनाओं को भड़काने का माध्यम बनती जा रही है। यह विभाजनकारी सोच असम की उस समृद्ध परंपरा के खिलाफ है, जिसने हमेशा विभिन्न समुदायों को साथ लेकर चलने की सीख दी है।

जरूरत इस बात की है कि हम इतिहास को समझें, तथ्यों को स्वीकार करें और समाज को बांटने के बजाय जोड़ने की दिशा में सोचें। असम केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि साझा विरासत है-और इस विरासत में हर उस व्यक्ति का हिस्सा है, जिसने इसे अपना घर माना।

साप्ताहिक राशिफल

27 मार्च से 2 अप्रैल 2026 ।। विक्रम संवत 2083-**मास** : चैत्र, **पक्ष** : शुक्ल, **तिथि** : नवमी

मेश राशि के जातकों को करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी और पदोन्नति के योग बन सकते हैं।

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय परिवर्तन का संकेत दे रहा है। करियर में बदलाव या नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक रूप से अचानक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना जरूरी होगा।

सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय नेतृत्व और सफलता का रहेगा। करियर में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें वे सफलतापूर्वक निभाएंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा और निवेश सोच-समझकर करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी रहेगा। रिश्तों में बेहतर संवाद से सामंजस्य बना रहेगा।

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय संतुलन और सहयोग का रहेगा। कार्यक्षेत्र में साझेदारी से लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य के लिए तनाव से बचना जरूरी होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन वे अपनी मेहनत और दृढ़ता से सफलता प्राप्त करेंगे।

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा। करियर में यात्रा के अवसर मिल सकते हैं और नए आय स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशि के लोगों के लिए यह समय मेहनत और धैर्य का है। करियर में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

मीन राशि के लोगों के लिए यह समय रचनात्मकता और सफलता का रहेगा। करियर में नए विचारों से लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

27 मार्च : शुक्रवार : नवरात्र व्रत पारण

29 मार्च : रविवार : कामदा एकादशी व्रत

31 मार्च : मंगलवार : श्री महावीर जयंती (जैन)

1 अप्रैल : बुधवार : पूर्णिमा व्रत

2 अप्रैल : गुरुवार : हनुमान जयंती

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

विपक्ष कहीं नहीं, भाजपा को मिलेगा प्रचंड जनादेश : हिमंत

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि राज्य में विपक्ष पूरी तरह कमजोर और जमीनी स्तर पर लगभग नदारद है।

नगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भाजपा के प्रति जनता का समर्थन काफी मजबूत हुआ है और इस बार पार्टी को भारी बहुमत मिल सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि संभव हुआ तो जनता भाजपा को 126 से भी अधिक सीटें देने का मन बना चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'सादिया से धुबड़ी और बराक घाटी से ब्रह्मपुत्र घाटी तक कहीं भी विपक्ष की सक्रियता नजर नहीं आती। मुझे तो विपक्ष के बारे में तब ही पता चलता है जब मैं मीडिया से बात करता हूं।' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक और सशक्त हो चुके हैं और इस बार वे पूरी दृढ़ता के साथ मतदान करेंगे।

प्रतीक नहीं, उम्मीदवार को दें वोट : जयंत दास

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

दिसपुर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे जयंत कुमार दास ने मतदाताओं से अपील की है कि वे पार्टी के चुनाव चिह्न के बजाय उम्मीदवार की कार्यक्षमता और जनसेवा को ध्यान में रखकर मतदान करें। जयंत दास ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान तभी संभव है, जब लोग व्यक्ति के काम और प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें क्षेत्र में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है और वे जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं।

उन्होंने भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि 'सिर्फ एक व्यक्ति' उनके टिकट कटने के लिए जिम्मेदार है। दास के अनुसार, वे 1990 से पार्टी से जुड़े रहे हैं और वर्षों तक संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्हें चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अंतिम समय में टिकट नहीं दिया गया। जयंत दास ने अपने पुराने राजनीतिक सफर को याद करते हुए बताया कि वर्ष 2006 में उन्होंने पार्टी के कहने पर जलुकबाड़ी सीट से चुनाव लड़ा था, जहां हार के बावजूद उन्होंने संगठन को मजबूत किया।

रंगाली बिहू उत्सव समिति का गठन

जन जन विचार
...✍ माजबाट

पूर्व मजबाट खारामखा में इस वर्ष भी रंगाली बिहू उत्सव मनाने के लिए एक सार्वजनिक बैठक में समिति का गठन किया गया। 19 मार्च को नवज्योति युवक संघ एवं पुस्तकालय के अध्यक्ष जतिन नाथ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सात दिवसीय कार्यक्रम के साथ बिहू उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में असम स्तर पर खुली बिहू प्रतियोगिता आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इसमें भाग लेने के इच्छुक दल 6002965281, 8638164317 और 9957836238 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

उत्सव को सफल बनाने के लिए विभिन्न उप-समितियों का गठन किया गया तथा स्थानीय जनता से सहयोग की अपील की गई। साथ ही, बैठक में पिछले वर्ष के आय-व्यय का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया गया।

असम के लोक भवन में मना बिहार स्थापना दिवस

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित लोक भवन में बिहार स्थापना दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भागीदारी देखने को मिली।

राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक समृद्धि और देश के विकास में उसकी अहम भूमिका पर प्रकाश डाला गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि बिहार और असम के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते बेहद गहरे हैं, जो देश की एकता को मजबूत करते हैं।

वक्ताओं ने बिहार की शिक्षा, साहित्य, कृषि और कला के क्षेत्र में उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य ने हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। साथ ही असम में रह रहे बिहार मूल के लोगों के योगदान की भी सराहना की गई।

कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। लोक गीत और नृत्य के जरिए बिहार की परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए इस तरह के आयोजनों के माध्यम से आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करने का संदेश दिया।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

सेंट्रल गुवाहाटी में तपिश

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 4 मई को मतगणना के साथ परिणाम सामने आएंगे।

किसका पलड़ा भारी ?

राजनीतिक विश्लेषकों के शुरुआती आकलन में भाजपा उम्मीदवार को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन यह भी सच है कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

निर्णायक फैक्टर : भाजपा का मजबूत संगठनात्मक ढांचा, विजय गुप्ता का लंबा राजनीतिक अनुभव, कुंकी चौधरी की युवा अपील, कांग्रेस गठबंधन का समर्थन व शहरी मतदाताओं का रुझान।

सेंट्रल गुवाहाटी सीट पर इस बार चुनाव केवल दो उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि अनुभव और बदलाव की सोच के बीच है। जहां एक ओर संगठन और अनुभव की मजबूती है, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी की उम्मीदें और बदलाव की चाह।

अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 अप्रैल को मतदाता किसे चुनते हैं-स्थिरता या परिवर्तन।

बिहार : 14 अप्रैल...

में शपथ लेने की तैयारी।

जदयू की लगातार बैठकें- नई सरकार के स्वरूप, सत्ता संतुलन और पदों के बंटवारे पर मंथन।

नीतीश का प्लान

दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका- राज्यसभा जाने का मतलब साफ है, राष्ट्रीय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप। यह संकेत हो सकता है कि नीतीश कुमार अब बिहार से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका चाहते हैं।

बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी- चर्चा है कि 14 अप्रैल (खरमास के बाद) नया मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है, तब तक नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। संभावित चेहरों में उनके बेटे निशांत कुमार का नाम भी चर्चा में है।

जदयू की नई सौदेबाजी- विधानसभा अध्यक्ष पद पर दावा, सरकार के गठन में जदयू की भूमिका मजबूत करना, एनडीए के भीतर संतुलन साधना,

खरमास का सियासी असर : भारतीय परंपरा में खरमास को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए, नई सरकार का गठन 14 अप्रैल के बाद होगा। यह धार्मिक-सांस्कृतिक कारण भी राजनीतिक टाइमिंग तय कर रहा है। नीतीश कुमार का यह कदम कई स्तरों पर समझा जा सकता है-

सेफ एग्जिट प्लान मुख्यमंत्री पद से सम्मानजनक दूरी बनाते हुए राष्ट्रीय भूमिका लेना।

पारिवारिक उत्तराधिकार नई पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करना। **गठबंधन राजनीति**- एनडीए के भीतर अपनी उपयोगिता बनाए रखना।

संपादकीय

हथियारों की होड़

दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां सुरक्षा के नाम पर बढ़ती हथियारों की होड़ स्वयं असुरक्षा को जन्म दे रही है। आज लगभग हर देश अपने सैन्य बजट में लगातार वृद्धि कर रहा है, लेकिन इससे शांति नहीं, बल्कि अविश्वास का वातावरण बन रहा है। एक देश की सैन्य शक्ति दूसरे देश को और अधिक हथियार जुटाने के लिए प्रेरित करती है, और यही क्रम वैश्विक तनाव को गहराता जा रहा है।

पश्चिम एशिया से लेकर रूस-यूक्रेन तक के संघर्ष यह संकेत दे रहे हैं कि युद्ध अब सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सामाजिक स्थिरता तक फैल रहा है। तेल की कीमतों में संभावित उछाल, महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा सीधे आम जनता को प्रभावित करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हथियारों पर बढ़ता खर्च वास्तव में मानवता के हित में है?

वास्तविकता यह है कि हथियारों पर खर्च किया गया धन शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों से संसाधन छीन लेता है। यदि यही संसाधन मानव विकास पर लगाए जाएं, तो दुनिया अधिक सुरक्षित और समृद्ध बन सकती है। इतिहास भी गवाह है कि युद्ध केवल विनाश, अस्थिरता और पीढ़ियों तक चलने वाले संकट ही छोड़ता है।

आज जरूरत है कि विश्व समुदाय शक्ति प्रदर्शन की मानसिकता से ऊपर उठकर संवाद, सहयोग और कूटनीति का मार्ग अपनाए। भारत जैसे देश, जिनकी पहचान शांति और सहअस्तित्व की परंपरा से जुड़ी है, इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हथियारों की नहीं, शांति की दौड़ ही मानवता के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है।

मानव जीवन की सार्थकता

यदि इस नश्वर शरीर से किसी का उपकार, कल्याण या पोषण न हो सके, तो यह दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ माना जाता है।

किंतु प्रश्न यह है कि वास्तविक कल्याण क्या है?

अन्न, वस्त्र, आवास और औषधि-ये केवल शरीर की क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अस्थायी सुख प्रदान करते हैं। यह पूर्ण परोपकार नहीं है।

सबसे बड़ा दया-धर्म और लोक-कल्याण तो जीव को उसके परम पिता श्री कृष्ण से पुन: मिलाना है। हमारे जन्मदाता माता-पिता हमें इस भौतिक संसार में लाते हैं, किंतु एक प्रचारक/ गुरु हमें इस दुखालयम् से मुक्त कर भगवान के परम सुखमय धाम की ओर ले जाते हैं।

वास्तविक कल्याणकर्ता वही है जो हमें हमारे स्वरूप का बोध कराए कि हम केवल कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए ही हैं।

इस देह को धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र उद्देश्य भगवान श्री हरि के नाम, गुण, लीलाओं और हरि भक्ति का प्रचार-प्रसार करना होना चाहिए।

यदि हम अपने संपूर्ण जीवनकाल में एक भी जीवात्मा को माया के जाल से छुड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा सकें, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता और सार्थकता होगी।

धर्म और जाति पर सुप्रीम आदेश

जन जन विचार
...✍ कमलेश पांडे

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से बाहर जाकर धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। दरअसल, आंध्र प्रदेश के एक धर्मांतरित ईसाई पादरी से जुड़े मामले में आए इस नवीनतम फैसले के व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। इससे हिंदू समुदाय के दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाकर धर्मांतरित करवाये जाने का पूरा खेल ही अब हतोत्साहित हो जाएगा।

हालांकि, कांग्रेस व समाजवादी मूल की क्षेत्रीय पार्टियां यदि चाहें तो इस मुद्दे पर अपनी राजनीति भी शुरू कर सकती है कि जब हिंदू, बौद्ध या सिख बनेंगे तो उनका एससी/ओबीसी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन जैन, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि बनने पर नहीं, यह कौन सा खिचड़ी न्यायिक दर्शन हैं, जो हर गतिरोध के बाद एक नया गतिरोध पैदा कर देता है। कहने का तातपर्य यह कि ज्यूडिशियल एंटीबायोटिक पॉवर बढ़ाए बिना संबंधित व्यक्ति या समूह का कल्याण नहीं होने वाला है।

कांग्रेस व समाजवादी मूल की क्षेत्रीय पार्टियां यदि चाहें तो इस मुद्दे पर अपनी राजनीति भी शुरू कर सकती है कि जब हिंदू, बौद्ध या सिख बनेंगे तो उनका एससी/ओबीसी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन जैन, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि बनने पर नहीं, यह कौन सा खिचड़ी न्यायिक दर्शन हैं, जो हर गतिरोध के बाद एक नया गतिरोध पैदा कर देता है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 23-24 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म (जैसे ईसाई, इस्लाम आदि) में परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। इस आदेश से एससी/एसटी आरक्षण लाभ और अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण खत्म हो जाता है। दरअसल, यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के आदेश पर आधारित है, जहां एक ईसाई पादरी को एससी/एसटी एक्ट के तहत संरक्षण से वंचित किया गया। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल निर्दिष्ट धर्मों के अनुयायी ही एससी लाभ ले सकते हैं। ईसाई या इस्लाम अपनाने पर जातिगत पहचान और लाभ दोनों समाप्त हो जाते हैं।

इस फैसले के अहम राजनीतिक मायने हैं। यह फैसला धर्मांतरण पर आधारित आरक्षण दावों को रोक सकता है, जो दक्षिणपंथी दलों के लिए समर्थन बढ़ाएगा। वहीं, अल्पसंख्यक आरक्षण बहस (जैसे दलित ईसाई/मुस्लिम) को प्रभावित कर चुनावी राजनीति में हिंदू एकता पर जोर देगा। राज्य सरकारें ओबीसी/एससी सूचियों की समीक्षा के दबाव में आ सकती हैं। वहीं, इस फैसले के बाद धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़ी बहस जोर पकड़ सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आलोक में फैसला दिया है, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते है जहां कानून और जमीनी हकीकत आमने-सामने आ जाते हैं। भारत में जाति एक सच्चाई है, जिसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इससे जुड़ी बुराइयों को खत्म करने की तमाम कोशिश होनी चाहिए। जो राजनीतिक और न्यायिक अदूरदर्शिता वश नहीं हो पा रही है और तरह तरह के संवैधानिक विवाद जन्म ले रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों को लगातार धक्का लग रहा है।

जहां तक इस फैसले के सामाजिक प्रभाव की बात है तो धर्म परिवर्तन के बाद एससी/ओबीसी का लाभ न मिलने से सामाजिक न्याय की नीति मजबूत होगी, लेकिन धार्मिक रूपांतरण रोकने या जातिगत अस्मिता पर बहस तेज हो सकती है। चूंकि दलित समुदायों में हिंदू/सिख/बौद्ध रहने का दबाव बढ़ेगा, जबकि ईसाई/मुस्लिम समुदायों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आरक्षण को ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। इस पर मौजूदा मोदी सरकार के वैचारिक असर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार दलित/ओबीसी हिंदुओं की एकजुटता व समग्र उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

हालांकि देश में जाति से जुड़ा सवाल बहुत टेढ़ा और जटिल है। क्योंकि सामाजिक स्तर पर हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि क्या धर्म बदलने भर से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है? गाहे बगाहे ऐसे मामले सामने आते रहे है, जिनमें दलित या ओबीसी समुदाय के लोगों को दूसरा धर्म अपनाने के बाद भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पिछले साल मार्च में ही तमिलनाडु के कुछ ईसाई परिवारों, जो पहले दलित थे, ने आरोप लगाया था कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। यहां तक कि कब्रिस्तान में उनके लोगों के शवों को दफनाने के लिए भी अलग जगह है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत के फैसले का आधार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 है। जिसका क्लॉज 3 कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही एससी श्रेणी में आ सकते है। धर्म परिवर्तन और जाति से जुड़ी यह बहस बहुत पुरानी है। इसके दो पहलू है। एक, जिन धर्मो में जाति व्यवस्था नही है, उन्हें अपनाकर फिर जाति से जुड़े लाभ कैसे लिए जा सकते है। पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े लाभ छोड़ दिए हों।

तब हाईकोर्ट ने कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति समुदाय को मिलने वाले फायदे लेते रहना संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास इस तरह की कई शिकायतें है और उसने पिछले साल देशभर में जांच भी शुरू की थी। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि संविधान के तहत मिले अधिकार का दुरुपयोग न होने पाए। क्योंकि जाति और धर्म का दुरुपयोग होने की चिंता शुरू से ही न्यायिक विमर्श का मुद्दा बनी हुई है। लिहाजा ब्रेक के बाद न्यायदेश मिलते रहते हैं।

इंद्रा साहनी केस (1992) मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण पर केंद्रित था, लेकिन हालिया सुप्रीम कोर्ट फैसले (धर्म परिवर्तन पर एससी दर्जा समाप्ति) से इसका अप्रत्यक्ष संबंध है। दोनों आरक्षण को जाति-आधारित ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने के सिद्धांत साझा करते हैं। इंद्रा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27फीसदी आरक्षण मान्य किया, लेकिन 50प्रतिशत कुल सीमा तय की और स्पष्ट किया कि आरक्षण का आधार धर्म या जाति अकेला नहीं हो सकता। क्रीमी लेयर बहिष्कार और पिछड़ापन के सामाजिक-शैक्षिक मापदंड निर्धारित किए गए।

हालिया फैसले से संबंध : 2026 के एससी/एसटी फैसले में संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 का हवाला दिया गया, जो इंद्रा साहनी के सिद्धांतों से मेल खाता है कि आरक्षण धर्म पर आधारित नहीं। ओबीसी मामलों में (जैसे मुस्लिम आरक्षण रद्द), कोर्ट ने इंद्रा साहनी का जिक्र कर धर्म को आधार बनाने से रोका, जो एससी केस की भावना से जुड़ता है। हालांकि, सीधा उल्लेख नहीं मिला, लेकिन सामान्य आरक्षण दर्शन समान है, जिसका सर्वकालिक महत्व जगजाहिर है।

पेट्रोल-डीजल व एलपीजी की कोई कमी नहीं : केंद्र

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में पेट्रोलियम और एलपीजी (एलपीजी) की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे %भ्रामक और दुष्प्रचार% पर ध्यान न दें, जिसका उद्देश्य बेवजह घबराहट पैदा करना है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास कुल मिलाकर 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और भूमिगत रणनीतिक भंडारण (कवर्न) शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि मध्य पूर्व संकट के 27वें दिन भी देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है।

सरकार ने कहा, हर भारतीय के लिए लगभग दो महीने की निरंतर आपूर्ति उपलब्ध है, चाहे वैश्विक परिस्थितियां कैसी भी हों। साथ ही अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद भी पहले ही सुनिश्चित कर ली गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कुछ देशों में जहां ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि, राशनिंग, ऑड-ईवन नियम और पेट्रोल पंप बंद होने जैसी स्थिति है, वहीं भारत में ऐसी किसी भी आपातकालीन उपाय की जरूरत नहीं है।

देश में 60 दिन का तेल भंडार मौजूद

पेट्रोल पंप मालिकों को राहत, क्रेडिट सीमा 3 दिन बढ़ाई

सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ जगहों पर घबराहट में ईंधन खरीदने की घटनाएं सामने आईं, लेकिन सरकार ने इसे सोशल मीडिया पर फैलाए गए भ्रामक वीडियो का परिणाम बताया। इसके बावजूद सभी उपभोक्ताओं को ईंधन उपलब्ध कराया गया और तेल कंपनियों ने रातभर डिपो चलाकर सप्लाई बढ़ाई। सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों को राहत देते हुए क्रेडिट सीमा 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दी है, ताकि कार्यशील पूंजी की कमी के कारण किसी भी पंप पर ईंधन की कमी न हो।

मंत्रालय ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की मौजूदा स्थिति के बावजूद भारत को अपने 41 से अधिक वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से पहले की तुलना में अधिक कच्चा तेल मिल रहा है। देश की सभी रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर चल रही हैं और अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले से तय है।

एलपीजी आपूर्ति भी पूरी तरह सुरक्षित

एलपीजी को लेकर भी सरकार ने किसी तरह की कमी से इनकार किया है। मंत्रालय के अनुसार, घरेलू उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे रोजाना उत्पादन 50 हजार मीट्रिक टन(टीएमटी) तक पहुंच गया है, जो कुल आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक है। अब आयात की दैनिक जरूरत घटकर 30 टीएमटी रह गई है। इसके अलावा, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से 800 टीएमटी एलपीजी की खेप पहले से रास्ते में है, जो देश के 22 आयात टर्मिनलों पर पहुंचेगी।

समुद्र में सौदा : भारत का नया रणनीतिक दांव

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

मिडिल ईस्ट के उथल-पुथल भरे माहौल के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने वैश्विक ऊर्जा राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान से चीन जा रहे एलपीजी कार्गो को भारत ने बीच समुद्र में ही खरीद लिया। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की आक्रामक और दूरदर्शी रणनीति का संकेत है।

क्या है पूरा मामला ?

सूत्रों के अनुसार, यह एलपीजी से लदा जहाज मूल रूप से चीन की ओर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही भारत ने उसे खरीदकर अपनी सप्लाई चेन में शामिल कर लिया। यह खेप जल्द ही मंगलुरु पोर्ट पहुंचेगी, जहां इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बीच वितरित किया जाएगा।

2019 के बाद ईरान से पहली खरीद : अमेरिका की पाबंदियों में आंशिक ढील के बाद भारत ने 2019 के बाद पहली बार ईरान से एलपीजी खरीदी है। खास बात यह है कि इस सौदे का भुगतान रुपए में किया जाएगा- यह कदम डॉलर पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा बचाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

चीन को झटका, भारत को मजबूती : जिस कार्गो पर चीन की नजर थी, उसे बीच रास्ते में खरीद लेना एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। इससे साफ संकेत जाता है कि भारत अब केवल खरीदार नहीं, बल्कि ऊर्जा बाजार में सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है।

क्यों जरूरी था यह कदम ?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव (खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट के आसपास) ने तेल और गैस सप्लाई को अस्थिर कर दिया है। भारत जैसे देश, जो अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 फीसदी आयात करता है, के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है और इसकी लगभग 90 फीसदी सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है। ऐसे में सप्लाई में किसी भी बाधा का सीधा असर आम उपभोक्ता और उद्योग दोनों पर पड़ता है।

आगे क्या संकेत ?

भारत पहले ही अपने फंसे टैंकरों को सुरक्षित निकालने में जुटा है और वैकल्पिक सप्लाई चैन मजबूत कर रहा है। यह ताजा कदम बताता है कि भारत अब 'रिएक्टिव' नहीं बल्कि 'प्रोएक्टिव' ऊर्जा नीति की ओर बढ़ रहा है।

रनोज पेगू ने गिनाईं योजनाएं

धेमाजी। असम सरकार के मंत्री डॉ. रनोज पेगू ने धेमाजी जिले के अरुणाचल प्रदेश सीमा से सटे आदिकोलीया गांव से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए क्षेत्र की पिछड़ेपन की समस्या को प्रमुखता से उठाया और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं और इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने जानकारी दी कि पहाड़ी क्षेत्रों को सिलापथार से जोड़ने वाली सड़क परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इस सड़क के बनने से स्थानीय लोगों के आवागमन में काफी सहूलियत होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए पेगू ने कहा कि लखीपाथार, उत्तर धेमाजी और बिशनुपुर जैसे इलाकों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क संपर्क और शिक्षा ढांचे का विस्तार ही सीमावर्ती व दूरदराज क्षेत्रों के समग्र विकास की कुंजी है। चुनावी माहौल के बीच धेमाजी में बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा प्रमुख मुद्दे बनकर उभर रहे हैं।

विचार

गलतियां हमें सिखाती हैं, इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए।

लघु कथा

लालच का फल

एक जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। उसे खाने का बहुत शौक था, खासकर मूंगफली का। एक दिन उसे एक घड़ा मिला, जिसमें मूंगफली भरी हुई थी।

बंदर ने खुशी-खुशी अपना हाथ घड़े में डालकर मुट्ठी भर मूंगफली पकड़ ली। लेकिन जब उसने हाथ बाहर निकालना चाहा, तो उसका हाथ फंस गया।

वह जोर-जोर से खींचने लगा, लेकिन हाथ बाहर नहीं आया। असल में, मुट्ठी में ज्यादा मूंगफली होने के कारण हाथ घड़े के मुंह से नहीं निकल पा रहा था।

पास से गुजरते एक बूढ़े कछुए ने कहा, 'अगर थोड़ी मूंगफली छोड़ दो, तो हाथ आसानी से निकल जाएगा।'

बंदर ने पहले तो नहीं माना, लेकिन थककर उसने कुछ मूंगफली छोड़ दी। जैसे ही उसने मुट्ठी ढीली की, उसका हाथ बाहर आ गया।

बंदर को अपनी गलती समझ आ गई।

पहेलियां

1. ऐसी कौन-सी चीज है, जो पानी पीते ही मर जाती है?

2. वह क्या है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना मुंह के बोलता है?

3. ऐसी कौन-सी चीज है, जिसे हम जितना निकालते हैं, वह उतनी ही बड़ी होती जाती है?

4. ऐसी कौन-सी चीज है, जो खुद तो चलती नहीं, लेकिन हमें चलाती है?

5. वह क्या है जो सुबह चार पैरों पर, दोपहर में दो पैरों पर और शाम को तीन पैरों पर चलता है?

उत्तर : आग, हवा, गड्ढा, घड़ी, इंसान (बचपन, जवानी, बुढ़ापा)

हाथी और चूहे

एक समय की बात है, एक शांत झील के किनारे एक भव्य और जीवंत शहर बसा हुआ था। लेकिन समय के साथ, लोग अपने जानवरों के साथ वहां से चले गए। केवल चूहे ही पीछे रह गए, जो उस खाली शहर में खुशी-खुशी रहते थे और पेड़ों से फल और सब्जियां खाते थे। जल्द ही वह शहर चूहों का शहर बन गया, जहां कई परिवार एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह एक साथ रहते थे।

पास ही एक जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था । एक गर्मी के मौसम में जंगल की नदी सूख गई। प्यासे हाथी पानी की तलाश में निकले और आखिरकार उन्हें चूहों के शहर के पास एक झील मिल गई। उत्साहित होकर हाथी पानी की ओर दौड़े, लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने गलती से कई चूहों को कुचल दिया।

चूहे दुखी और डरे हुए थे कि उनके लौटने पर और भी हाथी घायल हो जाएंगे। इसलिए, एक बूढ़े चूहे ने रानी हाथी से बात करने का सुझाव दिया। जब उन्होंने रानी को सारी घटना बताई, तो रानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वादा किया कि अगली बार झुंड दूसरा रास्ता अपनाएगा।

कुछ महीनों बाद, शिकारियों ने छिपे हुए जालों का इस्तेमाल करके कुछ हाथियों को पकड़ लिया और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। रानी हाथी, जो खुद भी पकड़ी गई थी, को चूहों का वादा याद आया। उसने मदद मांगने के लिए एक युवा हाथी को भेजा।

यह खबर सुनते ही हजारों चूहे जंगल की ओर दौड़ पड़े। अपने नुकीले दांतों से उन्होंने झटपट रस्सियों को कुतर दिया और हाथियों को मुक्त कर दिया।

हाथी की रानी ने चूहों को धन्यवाद दिया, और उस दिन से हाथी और चूहे जीवन भर के लिए दोस्त बन गए।

माँ शुतुरमुर्ग की मदद करें...

अंतर खोजो...

दिमाग लगाइए और सही उत्तर बताइए।

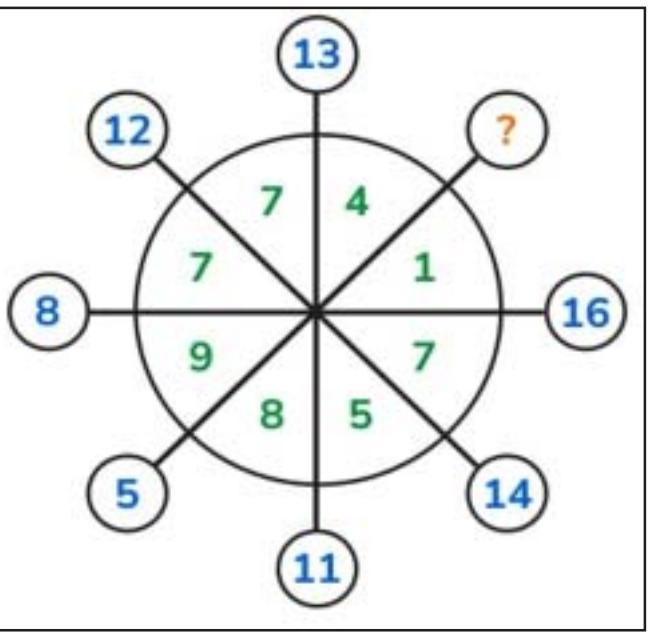

बिंदुओं को जोड़कर चित्र को पूरा कीजिए और रंग भरिए।

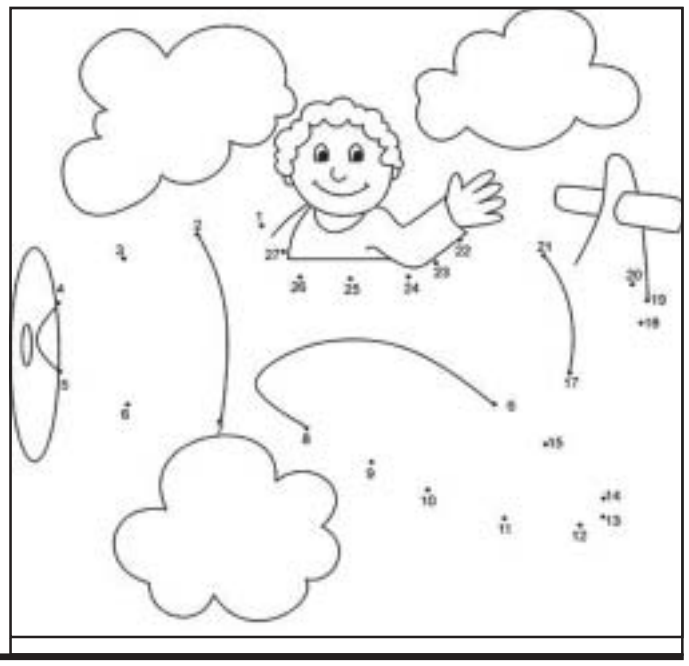

चुनावी शोर बनाम जमीन की सच्चाई

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव केवल प्रचार, रैलियों और नारों का खेल नहीं है, बल्कि यह 'जमीन की नब्ज' को समझने की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। इस समय असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन असली सवाल वही पुराना है-क्या हवा सच में वोट में बदलेगी, या जमीन पर कुछ और ही कहानी लिखी जा रही है?

असम : सत्ता का आत्मविश्वास बनाम विपक्ष की चुनौती

असम में भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से मजबूत स्थिति में है। डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने न केवल संगठन को मजबूत किया है, बल्कि विकास और पहचान की राजनीति को भी अपने पक्ष में साधने की कोशिश की है। सड़क, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के मुद्दों के साथ-साथ बांग्लादेशी घुसपैठ और असमिया अस्मिता जैसे विषय चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं।

लेकिन जमीन पर तस्वीर इतनी एकतरफा भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय समस्याएं अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भले ही कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन कई सीटों पर स्थानीय उम्मीदवारों की पकड़ मुकाबले को रोचक बना सकती है।

पश्चिम बंगाल : सीधी लड़ाई तीखा संघर्ष

पश्चिम बंगाल में मुकाबला अधिक स्पष्ट और आक्रामक है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि भाजपा इस बार निर्णायक बढ़त हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है।

भाजपा के लिए यह चुनाव 'करो या मरो' की स्थिति जैसा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले अप्रत्याशित समर्थन ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया, लेकिन विधानसभा चुनावों में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद पार्टी का वोट प्रतिशत स्थिर बना हुआ है, जो यह संकेत देता है कि जमीन पर उसकी पकड़ पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है।

वहीं ममता बनर्जी ने अपने जनाधार को मजबूत बनाए रखने के लिए कल्याणकारी योजनाओं और स्थानीय जुड़ाव पर जोर दिया है। महिला वोट बैंक, ग्रामीण समर्थन और संगठनात्मक जाल उनके लिए बड़ी ताकत साबित हो रहे हैं।

मुद्दों की राजनीति या भावनाओं की बिसात?

इन चुनावों में एक दिलचस्प पहलू यह है कि मुद्दे और भावनाएं दोनों समान रूप से प्रभाव डाल रहे हैं। असम में पहचान और सुरक्षा के मुद्दे हैं, तो बंगाल में सांस्कृतिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की बहस।

लेकिन यह भी सच है कि मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक हो चुका है। वह केवल बड़े-बड़े वादों या भाषणों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने दैनिक जीवन से जुड़े सवालों (रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई) को प्राथमिकता देता है।

संगठन बनाम करिश्मा : कौन भारी?

चुनावों में अक्सर यह बहस होती है कि क्या करिश्माई नेतृत्व ज्यादा असरदार होता है या मजबूत संगठन। असम में भाजपा का संगठनात्मक ढांचा और नेतृत्व दोनों संतुलित नजर आते हैं, जबकि कांग्रेस इस संतुलन की तलाश में है।

बंगाल में ममता बनर्जी का व्यक्तिगत करिश्मा और पार्टी का जमीनी नेटवर्क भाजपा के संगठित और संसाधन-संपन्न अभियान से टकरा रहा है।

जनता ही असली निर्णायक

चुनावी माहौल चाहे जितना भी गर्म क्यों न हो, अंतिम फैसला हमेशा मतदाता के हाथ में ही होता है। राजनीतिक दल हवा बनाने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जिसकी पकड़ जमीन पर मजबूत हो।

असम और पश्चिम बंगाल के ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या पुनरावृत्ति की कहानी नहीं हैं, बल्कि यह इस बात की भी परीक्षा हैं कि भारतीय लोकतंत्र में 'हवा' और 'जमीन' के बीच संतुलन किसके पक्ष में झुकता है।

आने वाले परिणाम यह तय करेंगे कि क्या प्रचार का शोर वास्तविक समर्थन में बदल पाया या फिर मतदाता ने अपनी चुप्पी में कोई अलग ही फैसला छुपा रखा था।

बंगाल में भाजपा का 'योगी मॉडल', उत्पल महाराज की एंट्री

जन जन विचार
...✍ कोलकाता

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही अपने अलग रंग और तेवर के लिए जानी जाती रही है। लेकिन इस बार चुनावी मुकाबले में एक नया और दिलचस्प मोड़ आया है-एक संन्यासी चेहरे की एंट्री, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर भाजपा ने बंगाल में एक नया प्रयोग शुरू किया है। यह प्रयोग है-उत्पल महाराज (स्वामी ज्योतिर्मयानंद) को चुनावी मैदान में उतारना। उत्तर दिनाजपुर की कालियागंज सीट से उनकी उम्मीदवारी केवल एक टिकट नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति का संकेत है।

कौन हैं उत्पल महाराज?

उत्पल महाराज, जिनका मूल नाम स्वामी ज्योतिर्मयानंद है, लंबे समय तक भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े रहे। सामाजिक सेवा और धार्मिक गतिविधियों के जरिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई।

लेकिन राजनीति में आने का उनका फैसला आसान नहीं था। संघ ने स्पष्ट रूप से उन्हें

निष्कासित कर दिया, क्योंकि संगठन खुद को गैर-राजनीतिक मानता है।

यहीं से यह कहानी केवल एक उम्मीदवार की नहीं, बल्कि 'धर्म बनाम राजनीति' के टकराव की भी बन जाती है।

भाजपा का यह कदम संयोग नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

हिंदू अस्मिता और पहचान की राजनीति को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली चेहरा खड़ा करना, उत्तर बंगाल में वोट बैंक को एकजुट करना।

यह रणनीति काफी हद तक योगी आदित्यनाथ के मॉडल से प्रेरित नजर आती है, जहां धार्मिक पहचान और राजनीतिक नेतृत्व का संयोजन सफल रहा।

ममता बनर्जी के सामने नई चुनौती

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए यह एक नई तरह की चुनौती है।

अब तक उनका मुकाबला मुख्यत: राजनीतिक और विकास के मुद्दों पर था, लेकिन अब उसमें भावनात्मक और धार्मिक आयाम भी जुड़ गया है।

संभावित प्रभाव : हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, उत्तर बंगाल में समीकरण बदलने की संभावना, तृणमूल की 'समावेशी छवि' पर सवाल।

जमीन की सच्चाई : क्या इतना आसान है खेल?

हालांकि यह रणनीति जितनी प्रभावशाली दिखती है, उतनी आसान नहीं है। बंगाल की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान बेहद मजबूत है। तृणमूल का जमीनी नेटवर्क गहरा और संगठित है। मतदाता केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि लाभकारी योजनाओं पर भी वोट करता है। यही कारण है कि विरोधी इसे भाजपा की 'सियासी चाल' करार दे रहे हैं और इसे आध्यात्मिक मूल्यों से विचलन भी बता रहे हैं।

उत्पल महाराज की एंट्री ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या वे बंगाल में भाजपा के 'योगी' बन पाएंगे? या यह प्रयोग भी बाकी रणनीतियों की तरह सीमित असर तक सिमट जाएगा?

ढेकियाजुली : विकास बनाम बदलाव की सीधी टक्कर

जन जन विचार
...✍ आनंद शर्मा
ढेकियाजुली

असम विधानसभा चुनाव 2026 के तहत 65 नंबर ढेकियाजुली विधानसभा सीट इस बार बेहद रोमांचक और बहुकोणीय मुकाबले का केंद्र बन गई है। कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिससे यहां सीधी लड़ाई के बजाय जटिल राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं और माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुका है।

मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और राज्य सरकार में मंत्री अशोक सिंहल तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार बतास उरांग के बीच माना जा रहा है। इसके अलावा वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के रंजय बसुमतारी सहित कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं, जो मुकाबले को त्रिकोणीय ही नहीं बल्कि बहुकोणीय बना रहे हैं।

भाजपा के अशोक सिंघल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को प्रमुख मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के दावे के साथ वे 'विकास और स्थिरता' को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। सत्ता पक्ष को भरोसा है कि इन उपलब्धियों के आधार पर मतदाता एक बार फिर उनका समर्थन करेंगे।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने बतास उरांग को मैदान में उतारकर चुनाव

में नई ऊर्जा भर दी है। उरांग का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। कांग्रेस इस चुनाव को 'बदलाव की लड़ाई' के रूप में पेश कर रही है और उरांग खुद को जमीनी नेता के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं।

ढेकियाजुली में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका बेहद निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में बतास उरांग का इसी समुदाय से होना कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण समीकरण बनाता है। हालांकि, वर्तमान समय में मतदाता केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि विकास, नेतृत्व क्षमता और उम्मीदवार की छवि को भी बराबर महत्व दे रहे हैं, जिससे मुकाबला और अधिक अनिश्चित हो गया है।

स्थानीय स्तर पर भी मतदाताओं के मुद्दे विविध हैं। एक वर्ग जहां मौजूदा सरकार के विकास कार्यों से संतुष्ट दिखता है और स्थिरता चाहता है, वहीं दूसरा वर्ग बदलाव और नई उम्मीदों की तलाश में है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव केवल दो दलों की लड़ाई नहीं, बल्कि 'विकास बनाम बदलाव' की सीधी परीक्षा है। भाजपा जहां अपने कामकाज और स्थिर शासन को मुद्दा बना रही है, वहीं कांग्रेस सामाजिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय जुड़ाव के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। साथ ही, निर्दलीय उम्मीदवार भी वोट कटवा बनकर नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। घर-घर संपर्क अभियान, जनसभाएं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने पूरे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। दोनों प्रमुख दल इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं।

अब सबकी निगाहें मतदाताओं के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। यह चुनाव तय करेगा कि ढेकियाजुली में जनता अनुभव और विकास पर भरोसा जताती है या बदलाव और नई उम्मीदों को मौका देती है। यह मुकाबला क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित होगा।

एक सड़क तय करेगी जनप्रतिनिधि का भाग्य

पेटुलीबाड़ी के लोग वर्षों से परेशान

जन जन विचार
...✍ नाजिरा

बिश्वनाथ जिला के अंतर्गत आने वाले कुंवरी पंचायत के 2 नंबर पेटुलीबाड़ी गांव में इस बार चुनावी चर्चा का केंद्र कोई बड़ा वादा नहीं, बल्कि एक जर्जर सड़क बन गई है।

वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, गांव के लोग जनप्रतिनिधियों के प्रति अपना आक्रोश खुलकर व्यक्त कर रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि पेटुलीबाड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से जोड़ने वाला यह संपर्क मार्ग हर बारिश में कीचड़ में तब्दील हो जाता है। हल्की सी बरसात होते ही सड़क पर चलना तक मुश्किल हो जाता है।

इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों और मरीजों पर पड़ता है। बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वहीं बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना किसी जोखिम से कम नहीं होता।

गांव के बुजुर्गों का कहना है, 'हर साल यही हाल रहता है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।'

ग्रामीणों के अनुसार, कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।

अब चुनाव सिर पर है और पेटुलीबाड़ी के लोगों का रुख साफ है,

'इस बार वोट उसी को मिलेगा, जो हमारी सड़क बनाएगा।'

स्पष्ट है कि इस बार बिश्वनाथ में यह सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला करने वाली कसौटी बन चुकी है।

राजनीतिक दलों ने दिखाया दमखम

जन जन विचार
...✍ बेददीप उपाध्याय
बिश्वनाथ चारिआली

विश्वनाथ चारिआली में असम विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई। प्रमुख राजनीतिक दलों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी चुनावी तैयारियों का दमखम दिखाया।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिश्वनाथ विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पल्लव लोचन दास और गोहपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार उत्पल बोरा ने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल

किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और खास बना दिया।

सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि बैजयंत जय पांडा स्वयं हेलीकॉप्टर उड़ाकर बिश्वनाथ पहुंचे, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया और समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया।

वहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस उम्मीदवार जयंत बोरा ने विशाल रैली के साथ नामांकन दाखिल किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए।

नाजिरा सीट पर 8 प्रत्याशी, मुकाबला रोचक

जन जन विचार
...✍ नाजिरा

ऊपरी असम के नाजिरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनाव कई मायनों में खास हो गया है। पहली बार यहां से रिकॉर्ड आठ प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है।

शिवसागर जिले के अंतर्गत आने वाली इस सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है। इसी क्षेत्र से चुनाव जीतकर स्वर्गीय हितेश्वर सैकिया ने मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया था। लंबे समय तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है, जहां सैकिया परिवार के तीन सदस्य विधानसभा तक पहुंचे।

हालांकि, वर्ष 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया। पिछले विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखा, जब भाजपा उम्मीदवार मयूर बरगोहाईं ने कांग्रेस के देबब्रत सैकिया को कड़ी टक्कर दी और बहुत कम मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।

इस बार भी भाजपा ने मयूर बरगोहाईं पर भरोसा जताया है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है।

यद्यपि मैदान में आठ उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। चुनावी माहौल में आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं-एक ओर वर्तमान विधायक पर विकास में निष्क्रियता के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने नाजिरा क्षेत्र के प्रति अपेक्षित इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

अब फैसला मतदाताओं के हाथ में है। वे किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजेंगे, यह जल्द ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार नाजिरा सीट पर मुकाबला न केवल कड़ा बल्कि बेहद रोचक भी होने जा रहा है।

दाने-दाने को तरसेगी दुनिया

महायुद्ध का साइड इफैक्ट

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब वैश्विक संकट का रूप लेता जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध जल्द नहीं थमा, तो दुनिया के सामने भुखमरी का भयावह संकट खड़ा हो सकता है।

4.5 करोड़ नए लोग भुखमरी की चपेट में

डब्ल्यूएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा हालात बने रहे तो करीब 4.5 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं।

इससे वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 36.3 करोड़ तक पहुंच सकती है-जो अब तक का सबसे चिंताजनक आंकड़ा है।

ईंधन संकट ने बढ़ाई महंगाई

मध्य एशिया में जारी संघर्ष का सबसे बड़ा असर तेल और ईंधन की कीमतों पर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने की आशंका है। परिवहन और खेती की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। फलस्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो सकती हैं।

टूटी सप्लाई चेन, बढ़ी मुश्किलें

युद्ध के कारण समुद्री और जमीनी व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं।

जरूरी सामानों की आपूर्ति में देरी

बाजारों में कमी और कृत्रिम महंगाई

दूर-दराज के देश भी संकट से अछूते नहीं

यानी युद्ध का असर सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है।

वैश्विक संकट में बदली जंग

इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा। यह एक वैश्विक मानवीय संकट बनता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी हो गया है।

शांति की कोशिशें तेज

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता के प्रयास जारी डोनाल्ड ट्रंप ने भी तनाव कम करने के संकेत दिए। कई देश युद्धविराम के लिए सक्रिय।

खत्म नहीं होगी जंग, ईरान का बातचीत से इनकार

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि वह अपनी प्रतिरोध की नीति पर कायम रहेगा और संघर्ष जारी रखेगा।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सरकारी टीवी पर कहा कि अब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और आगे भी बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत करना हार मानने जैसा होगा।

अमेरिका की चेतावनी

इससे पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान शांति के लिए तैयार नहीं होता, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि बातचीत की कोशिशें जारी हैं।

प्रस्ताव भी अस्वीकार

अमेरिका की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को भी ईरान ने अस्वीकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि यह प्रस्ताव उसकी शर्तों के अनुसार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र की अपील

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से युद्ध रोकने की अपील की है।

ईरान ने ठुकराया पाक का प्रस्ताव

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश विफल हो गई। ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि वह किसी बातचीत के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहल की थी, लेकिन उसे महत्व नहीं मिला। इस दौरान ईरान ने भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि उसके साथ संबंध सम्मानजनक हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान क्षेत्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती विश्वसनीयता को दर्शाता है, जबकि पाकिस्तान की भूमिका सीमित नजर आई।

ईएमआई के बोझ से राहत : सही योजना से पाएं आर्थिक संतुलन

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

आज के दौर में लोन और ईएमआई आम जरूरत बन चुके हैं, लेकिन बिना योजना के लिया गया कर्ज धीरे-धीरे आर्थिक बोझ में बदल जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आपकी कुल ईएमआई आपकी मासिक आय के 35-40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना वित्तीय असंतुलन बढ़ सकता है।

ईएमआई को संभालने के लिए सबसे पहले अपने सभी लोन की एक सूची बनाएं, जिसमें ब्याज दर, बकाया राशि और अवधि शामिल हो। इसके बाद सबसे अधिक ब्याज वाले कर्ज, जैसे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, को प्राथमिकता से चुकाएं। हर महीने 2000-5000 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने से कुल ब्याज में बड़ी बचत होती है।

अगर किसी दूसरे बैंक में कम ब्याज दर मिल रही हो, तो बैलेंस ट्रांसफर पर विचार किया जा सकता है। वहीं, लोन का प्रीपेमेंट ईएमआई

का बोझ कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। साल में एक अतिरिक्त ईएमआई जमा करने से लोन की अवधि कम हो जाती है।

साथ ही, 3-6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है, ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर नया कर्ज न लेना पड़े। सही बजट, अनुशासन और समझदारी से लिए गए फैसले ही आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं।

जन जन विचार
RNI Regd No. ASMUL/25/A2367
Head Office : Golapi Market, 1st Floor, Beltola, Guwahati 781028
Branch Office : JanJan Vichar, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati - 781005
Contact : 69001 26012
Email: official.janjanvichar@gmail.com
Website: WWW.janjanvichar.in

ग्राहक सदस्यता फॉर्म

ग्राहक विवरण
पूरा नाम : ....
पूरा पता : ....
मोबाइल : .... ह्वाट्सएप ....
ई-मेल (यदि हो) : ....

सदस्यता विवरण
अवधि : 1 वर्ष शुल्क : रु. 500/- मात्र

सदस्यता के साथ विज्ञापन लाभ
● सालभर (52 अंक) का अखबार निःशुल्क मिलेगा
● एक निःशुल्क विज्ञापन (10 सेमी. x 3 कॉलम)
● विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ग्राहक की सुविधा अनुसार

भुगतान विवरण
☐ यूपीआई ☐ बैंक ट्रांसफर
Bank Details
JAN JAN VICHAR
Bank : HDFC, Branch : Guwahati
A/C No. 50200116979015
IFSC : HDFC0000264
भुगतान तिथि : .... रसीद संख्या..........

घोषणा
मैं स्वेच्छा से जन जन विचार साप्ताहिक अखबार की एक वर्ष की सदस्यता ग्रहण करता/करती हूँ एवं सभी शर्तों से सहमत हूँ।

ग्राहक के हस्ताक्षर : तिथि :

कार्यालय उपयोग हेतु
सदस्यता क्रमांक: .... भुगतान प्राप्त रसीद संख्या.......... प्राप्तकर्ता का नाम : ....
तिथि : .... हस्ताक्षर : ....

विश्व पटल पर चमका भारत

क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों का परचम

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में देश के चार प्रमुख संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में स्थान बनाकर शिक्षा जगत में भारत की बढ़ती ताकत को प्रमाणित किया है।

इस सूची में आईआईटी, जेएनयू के साथ-साथ आईआईएम अहमदाबाद जैसे संस्थान शामिल हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से प्रबंधन और विपणन अध्ययन में आईआईएम अहमदाबाद का शीर्ष 50 में स्थान हासिल करना देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।

खनन और खनिज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (धनबाद) ने वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान प्राप्त कर भारत का गौरव बढ़ाया है। वहीं आईआईटी दिल्ली ने इस वर्ष सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए छह विषयों में शीर्ष 50 में जगह बनाई है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने इस बार विभिन्न विषयों में शीर्ष 50 में कुल 27 स्थान हासिल किए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में दोगुने से अधिक है। यह उपलब्धि देश के 12 संस्थानों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है और यह दर्शाती है कि भारत अब केवल संख्या ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता के स्तर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन शिक्षा में हो रहे सुधारों ने भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नई पहचान दिलाई है। आने वाले समय में शोध क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवाचार पर जोर भारत को शिक्षा के क्षेत्र में और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।

ध्यान भटकना रुकावट नहीं, आगे बढ़ने का संकेत

जन जन विचार
...✍ रामेश्वर शर्मा

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर यह माना जाता है कि काम के दौरान ध्यान भटकना कमजोरी या असफलता का संकेत है। लेकिन हालिया विचारों और विशेषज्ञों की राय कुछ और ही कहानी कहती है। काम के बीच ध्यान का भटकना एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है-और यही प्रक्रिया कई बार नए विचारों और बेहतर समझ का रास्ता भी खोलती है।

दरअसल, जब हम किसी काम में अटकते हैं या हमारा ध्यान इधर-उधर जाता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि हमारे दिमाग को थोड़ी राहत या नए दृष्टिकोण की जरूरत है। ऐसे समय में खुद को दोष देने की बजाय, थोड़ी देर का विराम लेकर दोबारा शुरुआत करना अधिक प्रभावी होता है।

उद्देश्य से जुड़ाव : काम को बनाएं अर्थपूर्ण

जब हम अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत मूल्यों और बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखते हैं, तो काम में गहराई और संतोष दोनों बढ़ते हैं। यह समझ कि हमारा हर छोटा प्रयास भी किसी बड़े परिणाम का हिस्सा है, प्रेरणा को भीतर से मजबूत बनाती है।

छोटे कदम, बड़ी सफलता

किसी भी बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना सफलता का सरल और कारगर तरीका है। हर छोटी उपलब्धि न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि आगे बढ़ने की ऊर्जा भी देती है। धीरे-धीरे यही छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं।

अपनी उपलब्धियों को पहचानें

अक्सर हम अपनी प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि हम अपनी छोटी-बड़ी सफलताओं को नियमित रूप से दर्ज करें, तो हमें अपनी मेहनत का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। यह न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि आगे के प्रयासों को भी प्रेरित करता है।

प्राथमिकताओं की समझ जरूरी

हर काम को एक साथ करने की कोशिश तनाव बढ़ाती है। जरूरी है कि हम यह तय करें कि कौन-सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। सही प्राथमिकताएं तय करने से न केवल काम आसान होता है, बल्कि समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग भी संभव होता है।

ध्यान का भटकना रुकावट नहीं, बल्कि एक संकेत है-रुककर सोचने, समझने और फिर से बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का। असली प्रेरणा बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की।

सेना में जवानों की तरक्की का नया दौर

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा में दिन-रात जुटे जवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अब अपने ही जवानों को अधिकारी बनाने की प्रक्रिया को आसान और तेज कर दिया है। इस बदलाव से खास तौर पर ग्रेजुएट जवानों के लिए अफसर बनने का सपना अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गया है।

पहले सेना में जवानों को आर्मी कैडेट कॉलेज के जरिए अधिकारी बनने के लिए 3 साल की पढ़ाई और 1 साल की ट्रेनिंग यानी कुल 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता था।

अब नए नियमों के तहत ग्रेजुएट जवानों के लिए यह अवधि घटाकर महज 1.5 साल कर दी गई है।

हालांकि 12वीं पास जवानों के लिए पुरानी व्यवस्था अभी भी लागू रहेगी।

सेना ने चयन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। करीब 10 साल का अनुभव रखने वाले जवानों को अब सीधे एसएसबी के स्टेज-2 में एंट्री दी जाएगी।

इससे उन्हें शुरुआती जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और वे सीधे अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा सकेंगे। टेक्निकल एंट्री स्कीम (टीईएस) के तहत ट्रेनिंग अवधि को 5 साल से घटाकर 4 साल कर दिया गया है।

दूरदर्शन गुवाहाटी में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी

युवाओं के लिए मीडिया क्षेत्र में कदम रखने का एक अच्छा अवसर सामने आया है। प्रसार भारती के अंतर्गत दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के जरिए वीडियो असिस्टेंट, रिसोर्स पर्सन, पोस्ट-प्रोडक्शन असिस्टेंट सहित कई पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी।

सबसे खास बात यह है कि इन पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती में मीडिया और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कई पद शामिल हैं-

रिसोर्स पर्सन : लेखन व भाषा कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता, प्रति असाइनमेंट 3000 रुपए। **वीडियो असिस्टेंट:** कैमरा संचालन व वीडियोग्राफी का कार्य, प्रति असाइनमेंट 5000 रुपए। **पोस्ट-प्रोडक्शन असिस्टेंट :** वीडियो एडिटिंग का काम, 3500 रुपए प्रति असाइनमेंट। **वेबसाइट/सोशल मीडिया एडिटर :** डिजिटल प्लेटफॉर्म संभालने की जिम्मेदारी, 3000 रुपए प्रति असाइनमेंट। **कैमरा असिस्टेंट :** 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। **सीजी ऑपरेटर व लाइब्रेरी/आर्काइव असिस्टेंट :** तकनीकी व रिकॉर्ड प्रबंधन से जुड़े कार्य।

यह भर्ती स्थायी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि पैनल तैयार करने के उद्देश्य से की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को आवश्यकता के अनुसार असाइनमेंट दिए जाएंगे और एक महीने में अधिकतम 7 कार्य ही मिल सकते हैं।

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हो सकता है। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

मीडिया, डिजिटल कंटेंट और प्रसारण के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। खासकर असम और पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए यह मौका स्थानीय स्तर पर अनुभव हासिल करने का मार्ग खोलता है।

आकाशवाणी गुवाहाटी में अंशकालिक उद्घोषक-उद्घोषिका के लिए आवेदन आमंत्रित

आकाशवाणी गुवाहाटी ने विभिन्न भाषाई एवं कार्यक्रम शाखाओं में अंशकालिक उद्घोषक-उद्घोषिका की नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। केवल गुवाहाटी नगर क्षेत्र के निवासी ही इसके लिए पात्र होंगे।

जिन शाखाओं में नियुक्ति की जाएगी, उनमें सामान्य घोषणा (असमिया भाषा), नेपाली, कार्बी, बोडो तथा चाय जनजाति कार्यक्रम शाखा शामिल हैं। प्रत्येक शाखा के लिए संबंधित भाषा का ज्ञान अनिवार्य माना जाएगा।

आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है, जबकि आयु सीमा 20 से 50 वर्ष रखी गई है (अंतिम तिथि के अनुसार)। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, वॉइस टेस्ट (कंठस्वर परीक्षण) तथा साक्षात्कार शामिल होंगे।

इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन शुल्क की रसीद के साथ 10 अप्रैल 2026 तक जमा करना होगा।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक शाखाओं में आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक शाखा के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

यह अवसर गुवाहाटी के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए आकाशवाणी जैसे प्रतिष्ठित मंच पर अपनी आवाज और प्रतिभा प्रस्तुत करने का एक सुनहरा मौका है।

हॉकी वर्ल्ड कप : पाक का ड्रामा शुरू

जन जन विचार
...✍ स्पोर्ट्स डेस्क

हॉकी में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल बन गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (पीएचएफ) ने साफ संकेत दिए हैं कि वह भारत के खिलाफ मैच खेलने के फैसले पर अपनी सरकार से सलाह लेगा। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान को 'पूल डी' में रखा गया है। दोनों टीमों के बीच 19 अगस्त को मुकाबला प्रस्तावित है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी तक स्पष्ट सहमति नहीं दी गई है।

खेल में राजनीति की छाया

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय खेल संबंध लंबे समय से बंद हैं, हालांकि दोनों देश बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में आमने-सामने होते रहे हैं। हाल के वर्षों में राजनीतिक तनाव के कारण कई बार ऐसे मुकाबलों पर संशय की स्थिति बनी है।

पाकिस्तान की चुनौतीपूर्ण स्थिति

पाकिस्तान हॉकी टीम का प्रदर्शन भी हाल के वर्षों में कमजोर रहा है। 2018 के बाद यह उनका पहला विश्व कप होगा। टीम लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रही है। हालिया दौरों में भी विवाद और समस्याएं सामने आई हैं

भारत का दबदबा

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले पांचों मुकाबले जीते हैं। 2022 एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था, जो दोनों टीमों के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है।

सीएसके में नई सोच, क्या लौटेगी पुरानी सफलता ?

जन जन विचार
...✍ स्पोर्ट्स डेस्क

आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अनुभव और स्थिरता के लिए जानी जाने वाली यह टीम अब युवाओं और नई रणनीति पर दांव लगा रही है। सवाल यही है-क्या यह नई सोच टीम को फिर से पुरानी सफलता दिला पाएगी ?

पिछला सत्र : गिरावट का दौर

सीएसके के लिए पिछला सत्र बेहद निराशाजनक रहा। टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही और 14 मुकाबलों में केवल 4 जीत दर्ज कर सकी। लगातार हार ने टीम की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए।

2026: नई शुरुआत, नया चेहरा

इस बार टीम ने बड़ा दांव खेलते हुए संजू सैमसन को शामिल किया है। यह कदम कहीं न कहीं 2008 में एमएस धोनी की एंट्री की याद दिलाता है, जिसने सीएसके की पहचान ही बदल दी थी।

सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड

युवाओं पर बड़ा भरोसा

सीएसके ने इस बार युवा खिलाड़ियों पर खुलकर निवेश किया है- प्रशांत वीर (20) व कार्तिक शर्मा (19)। दोनों पर भारी राशि खर्च करना इस बात का संकेत है कि टीम अब भविष्य को ध्यान में रखकर चल रही है। पिछले सत्र में आयूष मात्रे और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे युवा खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं देना इसी बदलाव की शुरुआत थी।

टीम संयोजन: आक्रामक लेकिन जोखिम भरा

संभावित अंतिम एकादश में अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण दिखता है- सैमसन, ऋतुराज गायकवाड, शिवम दुबे, ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, एमएस धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद।

यह संयोजन आक्रामक जरूर है, लेकिन स्थिरता की कमी भी साफ दिखती है।

गेंदबाजी सबसे बड़ी चिंता

सीएसके की असली परीक्षा उसके गेंदबाजी विभाग में होगी। रवींद्र जडेजा और सैम कुरैन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का जाना, अंतिम ओवरों के विशेषज्ञ की कमी और नए गेंदबाजों पर निर्भरता टीम को प्रयोग की स्थिति में ला सकती है।

धोनी का अंतिम सत्र ?

हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ा सवाल है-क्या यह एमएस धानी का अंतिम आईपीएल सत्र होगा ?

जोखिम बनाम परंपरा

सीएसके ने इस बार अपनी पारंपरिक 'अनुभव आधारित' रणनीति छोड़कर नई दिशा अपनाई है। अगर युवा खिलाड़ी सफल रहे तो टीम फिर से चैंपियन बन सकती है, लेकिन अगर प्रयोग असफल रहे तो अस्थिरता बढ़ सकती है।

सीएसके 2026 में एक 'ट्रांजिशन टीम' है-जहां विरासत और भविष्य आमने-सामने खड़े हैं। अब देखना यह है कि यह नई सोच उन्हें फिर से 'सुपर किंग्स' बनाती है या नहीं।

आईपीएल 2026 : ब्रांड वैल्यू की दौड़ में आगे आरसीबी

जन जन विचार
...✍ स्पोर्ट्स डेस्क

भारत में क्रिकेट केवल खेल नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक तंत्र बन चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी कुल व्यावसायिक कीमत लगभग 18.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में फ्रेंचाइजी टीमों की ब्रांड वैल्यू को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है।

2026 के ताजा आकलन के अनुसार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) 269 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। इसके पीछे मुंबई इंडियंस (एमआई) 242 मिलियन डॉलर और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) 235 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) 227 मिलियन डॉलर के साथ मजबूत स्थिति में बनी हुई है।

आरसीबी की यह छलांग उसके 2025 के पहले आईपीएल खिताब से जुड़ी मानी जा रही है। लंबे समय से बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद ट्रॉफी का अभाव था, लेकिन खिताब जीतते ही उसकी ब्रांड वैल्यू में लगभग 67फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल मैदान पर प्रदर्शन ही सब कुछ नहीं है। मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, डिजिटल पहुंच और वैश्विक विस्तार जैसे कारक भी टीमों की आर्थिक ताकत तय करते हैं।

रिपोर्ट बताती है कि चार टीमें (आरसीबी, एमआई, सीएसके और केकेआर) 200 मिलियन डॉलर से ऊपर की श्रेणी में हैं, जबकि बाकी छह टीमें 122 से 154 मिलियन डॉलर के बीच सीमित हैं। यह अंतर केवल खेल प्रदर्शन का नहीं, बल्कि वर्षों से बने व्यावसायिक ढांचे का परिणाम है।

इंपैक्ट प्लेयर नियम पर सवाल

नई दिल्ली/मुंबई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के आगाज से पहले मुंबई में आयोजित सभी फ्रेंचाइजियों के कप्तानों की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा बहस इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर देखने को मिली, जिस पर अधिकांश कप्तानों ने आपत्ति जताई।

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही इस नियम को लेकर खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। 2023 में लागू किए गए इस नियम को बीसीसीआई पहले ही 2027 तक जारी रखने का फैसला कर चुका है, जिससे कप्तानों की चिंता और बढ़ गई है।

ऑलराउंडरों के भविष्य पर चिंता : कप्तानों का मानना है कि इंपैक्ट प्लेयर नियम से टीम संयोजन में बदलाव आया है और इसका सबसे अधिक असर ऑलराउंडरों पर पड़ रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने स्पष्ट कहा कि इस नियम के कारण अब टीमों को ऑलराउंडर चुनने की जरूरत कम महसूस होती है। इससे पहले रोहित शर्मा भी इस नियम की आलोचना कर चुके हैं।

बीसीसीआई का रुख : बैठक में कप्तानों ने अपने सुझाव और आपत्तियां रखीं, लेकिन बीसीसीआई का रुख साफ रहा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस नियम की समीक्षा अब 2027 के बाद ही की जाएगी, उससे पहले इसमें बदलाव संभव नहीं है।

गेंद बदलने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं : बैठक में एक और अहम मुद्दा उठा-पहली पारी के 10 ओवर के बाद गेंद बदलने का प्रस्ताव। हालांकि, इसे ज्यादा समर्थन नहीं मिला।

वर्तमान में दूसरी पारी में ओस के प्रभाव को कम करने के लिए 10 ओवर बाद गेंद बदलने का नियम लागू है, जो आगे भी जारी रहेगा।

ट्रेनिंग नियम : कप्तानों ने 2026 सीजन के लिए जारी ट्रेनिंग गाइडलाइंस पर भी स्पष्टता मांगी। नए नियमों के अनुसार- मैच के दिन अभ्यास की अनुमति नहीं होगी। एक टीम के अभ्यास खत्म करने के बाद दूसरी टीम उसी विकेट पर अभ्यास नहीं कर सकेगी।

बॉक्स ऑफिस की आंधी और विवादों का तूफान

जन जन विचार
...✍ एंटरटेनमेंट डेस्क

बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' अब विवादों के घेरे में आ गई है। जहां एक ओर फिल्म कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसके कंटेंट को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है।

फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्य और कथानक को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि फिल्म में सुरक्षा एजेंसियों और पड़ोसी देश से जुड़े मुद्दों को जिस तरह पेश किया गया है, वह 'भ्रामक और अतिरंजित' है। कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे संवेदनशील विषयों के साथ खिलवाड़ बताया है और सेंसर बोर्ड से हस्तक्षेप की मांग की है।

फिल्म के निर्देशक आदित्य धर का कहना है कि 'धुरंधर 2' एक काल्पनिक कहानी है, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म किसी भी वास्तविक घटना या संस्था को लक्ष्य बनाकर नहीं बनाई गई है।

वहीं, विरोध के बीच फिल्म को लेकर समर्थन भी कम नहीं है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग इसे देशभक्ति और एक्शन से भरपूर 'मसाला एंटरटेनर' मानते हुए सराह रहा है।

'धुरंधर 2 : द रिवेंज'

फिल्म की कहानी

अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' एक हाई-ऑक्टेन जासूसी और एक्शन थ्रिलर है, जिसमें देशभक्ति, सस्पेंस और बदले की कहानी का दमदार मिश्रण देखने को मिलता है।

फिल्म की कहानी भारतीय खुफिया एजेंट हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक आतंकी-अपराधी नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। यह नेटवर्क देश के खिलाफ बड़े हमले की साजिश रच रहा होता है। हमजा को दुश्मन के इलाके में अंडरकवर जाकर घुसपैठ करनी पड़ती है।

मिशन और संघर्ष : दुश्मन के बीच रहकर अपनी पहचान छिपाना, खतरनाक अपराध सरगना तक पहुंच बनाना, अंदरूनी साजिशों और धोखे का सामना करना

जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमजा को पता चलता है कि यह मिशन सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि भीतरी विश्वासघात से भी जुड़ा है।

क्लाइमेक्स : फिल्म का अंत एक बड़े एक्शन और टकराव के साथ होता है, जहां-हमजा देश को एक बड़े खतरे से बचाने में कामयाब होता है, लेकिन इस मिशन की कीमत उसे व्यक्तिगत रूप से भारी चुकानी पड़ती है

फिल्म की कमाई

अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2 : द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। वीकेंड पर रिकॉर्डतोड़ कमाई के बाद फिल्म के लिए सोमवार का टेस्ट अहम माना जा रहा था, जिसमें यह फिल्म पास होती नजर आई।

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के पांचवें दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म ने करीब 34.10 करोड़ रुपए का कारोबार किया। हालांकि रविवार के मुकाबले कमाई में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन वीकडे की शुरुआत को देखते हुए इसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है।

फिल्म ने पहले चार दिनों में ही ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 400 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी।

पहले दिन : 145 करोड़ रुपए
दूसरे दिन : 80.72 करोड़ रुपए
तीसरे दिन : 113 करोड़ रुपए
चौथे दिन : 114.85 करोड़ रुपए

पांचवें दिन के बाद फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन लगभग 488.22 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। निर्देशक आदित्य धर की इस एक्शन-थ्रिलर का बजट करीब 250-300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसे फिल्म शुरुआती दिनों में ही पार कर चुकी है।

पवन सिंह को चाहिए तलाक

जन जन विचार
...✍ एंटरटेनमेंट डेस्क

भोजपुरी सिनेमा के 'पावरस्टार' पवन सिंह की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे तलाक मामले में अभिनेता ने अब खुलकर अलग होने की इच्छा जताई है।

कोर्ट में साफ कहा अब साथ नहीं रहना

25 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान पवन सिंह ने जज के सामने स्पष्ट कहा कि-

वह अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें तलाक चाहिए और वह वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी तैयार हैं।

हालांकि, इस अहम सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थीं।

मंदिर से कोर्ट तक

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनवाई से पहले पवन सिंह हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। इसके बाद वह कोर्ट पहुंचे। करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद जब वह बाहर निकले तो चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। मीडिया के सवालों पर उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर जवाब दिया।

ज्योति सिंह की अलग तस्वीर

सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह छठ महापर्व के अवसर पर सिंदूर लगाए नजर आईं और लोगों को शुभकामनाएं देती दिखीं।

केस का फैसला आने वाले समय में ज्योति सिंह की प्रतिक्रिया और कोर्ट की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा

गर्मी में बढ़ता है मलेरिया का खतरा

जन जन विचार
...✍ हेल्थ डेस्क

गर्मी शुरू होते ही मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है और इसके साथ ही मलेरिया के मामलों में भी तेजी से इजाफा देखने को मिलता है। यह सिर्फ एक सामान्य बुखार नहीं, बल्कि समय पर इलाज न मिले तो गंभीर एनीमिया, अंग फेलियर और मृत्यु तक का कारण बन सकता है।

गर्म तापमान और बढ़ी हुई नमी (ह्यूमिडिटी), जगह-जगह जलभराव (कूलर, बाल्टी, गमले, टंकी), खराब ड्रेनेज सिस्टम- ये सभी स्थितियां मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श माहौल बनाती हैं।

मलेरिया एक संक्रामक रोग है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के जरिए शरीर में पहुंचे परजीवी पहले लिवर में बढ़ते हैं, फिर खून में जाकर रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित करते हैं।

लक्षण: ठंड लगकर तेज बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द और बदन दर्द, कमजोरी, उल्टी, भूख न लगना।

बचाव : मच्छरों के पनपने से रोकें, मच्छरों के काटने से बचें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, रिपेलेंट क्रीम लगाएं, पूरे कपड़े पहने

इम्यूनिटी भी है जरूरी, पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, पूरी नींद लें।

पूर्वांचल प्रिंट्स की ओर से राजनाथ पाल द्वारा जीएमसीएच रोड, हरबाला मार्केट, भांगागढ़, गुवाहाटी-781005 से प्रकाशित एवं मुद्रित। संपर्क : 69001 26012
ई-मेल:official.janjanvichar@gmail.com, वेबसाइट: www.janjanvichar.in ●संपादक : धनेश्वर चौधरी